

भारत में हुआ असंगत और असमान विकास

जैसे जैसे आम चुनाव नजदीक आ रहा है वर्तमान सरकार के कार्यों की समीक्षा भी की जाने लगी है। जाहिर है सरकार के कार्य वभिन्न कसौटियों पर कसे जाएंगे। वर्तमान में चल रहे संसद के बजट अधविशन में राष्ट्रपतिका अभभाषण केवल इन्हीं मुद्दों पर केंद्रति था कि पछिले साढ़े चार वर्षों में सरकार ने क्या-क्या काम कयि। सरकार ने एक ठोस, मज़बूत, प्रगतशील राष्ट्र के नरिमाण में सहायक बजट की रूपरेखा पूरे देश के समकष रखी है।

व्यापारिक स्तर पर

- वशिव बैंक द्वारा जारी होने वाले **व्यापार सुगमता सूचकांक** (Ease of Doing Business-EDB) में वभिन्न देशों में व्यापार करने की सुविधाओं के बारे में जानकारी दी जाती है।

यह सूचकांक व्यापार के प्रतिसरकारी अधिकारियों, वकीलों, बज़िनेस कंसल्टेंट्स इत्यादि का रुख भी दर्शाती है। कारोबार शुरू करना, नरिमाण अनुमति, बजिली की उपलब्धता, संपत्तिका रजसि्टरेशन, ऋण की उपलब्धता, नविशकों की सुरक्षा, टैक्स अदायगी, सीमा पर व्यापार, कॉन्ट्रैक्ट्स का पालन, दवालयिपन से उबरने की शक़्ती जैसे आधारों पर इस सूचकांक में कसिी देश की रैंकिंग नरिभर करती है।

- सरकार ने इस दशिा में बेहतर प्रदर्शन करते हुए चार सालों में भारत को 57 रैंक ऊपर पहुँचाया है। जज़ातव्य है कि 2014 में भारत 134वें रैंक पर था, जबकि 2018 में 190 देशों में 77वें रैंक पर है।
- हालाँकि यह सूचकांक वशिव पटल पर वविादों में घरिा रहता है क्योँकि यह व्यापार सुगमता के लयि केवल सरकारी प्रयासों को ही आधार बनाता है, जबकि इसके अलावा कई ऐसे बदि हैं जनि पर कारोबार की सुगमता नरिभर करती है। ये बदि हैं- उत्पादकों को मलिनै वाली सेवाएँ, बजिली के साथ पानी की उपलब्धता, कचरा प्रबंधन आदि।

मानव संसाधन विकास के स्तर पर

- मानव विकास सूचकांक** (Human Development Index-HDI) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP द्वारा जारी कयिा जाता है।
- इस सूचकांक को पाकसितानी अरथशास्त्री महबूब उल हक एवं भारतीय अरथशास्त्री अमरृत्य सेन ने मलिकर वकिसति कयिा है।

इसमें प्रतियक़्ता आय, स्वास्थ्य एवं स्कूली शक़िषा के आधार पर वभिन्न देशों को रैंकिंग दी जाती है। यह सूचकांक विकास की गुणात्मकता की जानकारी तो देता है, लेकनि उसकी गुणवत्ता के बारे में मौन रहता है। जैसे केवल यह देखा जाना कि स्कूल में कतिने वदियार्थी हैं, काफी नहीं है; इसके साथ यह देखना भी जरूरी है कि उनहें मलिनै वाली शक़िषा की गुणवत्ता का स्तर कैसा है।

- पछिले चार सालों के आँकड़े देखने पर पता चलता है कि इस सूचकांक में भारत का स्थान जस-का-तस बना हुआ है।
- जहाँ 2014 में भारत का रैंक 130 था, वही 2018 में भी 130 ही है, जबकि भारत हालयिा वर्षों में सबसे तेजी से विकास करने वाली अरथव्यवस्था है।
- यह इस बात को दर्शाता है कि कसिी देश की अरथव्यवस्था मानव संसाधनों के मामले में उल्लेखनीय वृद्धि प्रापूत कयिा बनिा भी तेजी से आगे बढ़ सकती है।

पर्यावरण एवं पारस्थितिकी के स्तर पर

वशिव आरथकि मंच के साथ येल यूनिवर्सिटी एवं कोलंबयिा यूनिवर्सिटी द्वारा प्रकाशति कयिे जाने वाले **पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक** में 2018 में भारत को 180 देशों में 177वाँ रैंक मलिा। 2014 में भारत को 180 देशों में 155वें रैंक पर रखा गया था। इस सूचकांक में 24 संकेतकों के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। इनमें पर्यावरण स्वास्थ, पारस्थितिकी तंत्रों की वविधिता, वायु की गुणवत्ता, पेयजल एवं स्वच्छता, कृषि, जैववविधिता एवं जैव-आवास, जलवायु एवं ऊर्जा प्रमुख हैं।

- तुलनात्मक अध्ययन करने पर हम पाते हैं कि भारत पर्यावरण के मामले में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में से है।
- 2018 में तटीय आरथकि कषेत्र में उन स्थानों को भी नरिमाण एवं पर्यटन के लयि खोल दयिा गया है जनिहें पहले पवतिर एवं पारस्थितिकीय रूप से संवेदनशील माना जाता था।

उपरोक्त तीनों सूचकांकों का अध्ययन करने एवं इसमें भारत का प्रदर्शन देखने पर हम पाते हैं कि देश में एक तरफ तो कारोबारों के लिये सकारात्मक वातावरण तैयार हो रहा है कति दूसरी तरफ सामाजिक एवं पर्यावरण के स्तर पर लगातार या तो स्थिति जिस-की-तस बनी हुई है या और बगिड़ रही है।

इन सूचकांकों के अलावा भी बहुत से ऐसे करक हैं जो भारत के चहुँमुखी विकास को प्रभावित कर रहे हैं। इनमें गरीबी और बेरोज़गारी दो प्रमुख मुद्दे हैं। इसके अलावा कुछ सामाजिक चुनौतियाँ भी हैं जो राह में बाधा का कम करती हैं।

विकास तो हुआ, पर स्पष्ट गरीबी भी दखिती है

भारत के विकास को लेकर अमेरिकी अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता **पॉल करुगमैन** का कहना है कि आर्थिक मोर्चे पर भारत ने तेजी से प्रगति की है, लेकिन देश में कायम आर्थिक असमानता एक बड़ा मुद्दा है। लगातार बढ़ रही बेरोज़गारी भारत के विकास की राह में बाधक बन सकती है और यदि भारत के वनिरिमाण क्षेत्र के विकास की तेजी नहीं दिखाई दी तो इस संभावना को और बल मल्लिगा। हालाँकि पॉल करुगमैन ने भारत में हुए विकास की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारत ने पछिले 30 सालों में जतिनी आर्थिक प्रगति की है उतनी ग्रेट ब्रिटन को करने में 150 साल लग गए थे।

पहले की तुलना में भारत में कारोबारी सुविधाओं में इजाफा हुआ है, इसके बावजूद भारत में स्पष्ट दखि जाने वाली गरीबी भी है। भारत में आर्थिक असमानता का उच्च स्तर देखने को मल्लिता है, जो विकास के साथ बढ़ता ही गया है। इसके अलावा, देश में संपत्तिका असमान वितरण साफ दखिता है। आर्थिक सुधारों की वज़ह से देश ने तरक्की और विकास तो कयिा है, लेकिन एक-तहिाई आबादी अभी भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर कर रही है।

पॉल करुगमैन ने भारत की आर्थिक प्रगति को असाधारण बताया और कहा कि देश खरीदारी क्षमता के मामले में जापान से आगे निकल चुका है। चूँकि भारत में लाइसेंस राज रहा है, जहाँ नौकरशाही बाधाएँ बहुत हैं और इन्हें पूर्ण रूप से समाप्त कर पाना फलिहाल संभव भी नहीं है, फरि भी इसमें काफी कमी आई है और भारत में व्यापार करना पहले की तुलना में काफी आसान हो गया है।

विकास की राह में बड़ी बाधा है बेरोज़गारी

- एक रपिर्ट के अनुसार भारत में हर साल तकरीबन सवा करोड़ शक्ति युवा तैयार होते हैं। ये नौजवान रोजगार के लिये सरकारी और नज्जी क्षेत्रों में राह तलाशते हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश के हाथ असफलता ही लगती है।
- सरकारी क्षेत्र में नौकरियाँ लगातार कम होती जा रही हैं और नज्जी क्षेत्र में भी उन्ही लोगों को रोजगार मलि रहा है, जनिहें कसिी प्रकार का वशिषज्ज प्रशक्तिषण हासलि है।
- सबसे अधिक बेरोज़गारी ग्रामीण क्षेत्रों में है और यह देश के विकास में मुख्य बाधा है, क्योंकि इसकी वज़ह से बड़ी संख्या में गाँवों की ओर से शहरों के तरफ लोगों का पलायन हो रहा है।
- नए रोजगारों का सृजन करने में सरकार की वफिलता की वजह से बड़े पैमाने पर हो रहे इस पलायन की वजह से शहरों की अवसंरचना पर दबाव बढ़ रहा है।
- आधुनकित्ता के कारण परंपरागत संयुक्त परिवार टूट रहे हैं और नौकरी के लिये युवा लोगों ने शहरों का रुख कयिा है, और नौकरियाँ हैं नहीं।

सामाजिक चुनौतियाँ भी हैं बाधक

भारत ने 1990 के दशक में आर्थिक सुधार शुरू कयिे, उम्मीद थी कि इनसे लोगों के आर्थिक हालात सुधरेंगे, लेकिन शक्तिषा और स्वास्थ्य सेवाओं पर पर्याप्त ध्यान न देने की वज़ह से गरीबी, कुपोषण, भ्रष्टाचार और लैंगिक वषिमता जैसी सामाजिक समस्याएँ कम होने के बजाय बढ़ी हैं और देश के विकास को प्रभावित कर रही हैं।

जनसंख्या वसिफोट की स्थिति

- कसिी भी देश का आर्थिक विकास प्राकृतिक संसाधनों और जनसंख्या के आकार-प्रकार तथा कार्यक्षमता पर निर्भर करता है।
- जनसंख्या की दृष्टि से भारत का वशि्व में दूसरा स्थान है। आज देश की जनसंख्या का आँकड़ा करीब 135 करोड़ तक पहुँच गया है। वैश्विक आंकड़ों पर नज़र डालें, तो भारत वशि्व के 2.4 फीसद क्षेत्रफल पर वशि्व की 1.5 फीसद आय द्वारा 17.5 फीसद जनसंख्या का पालन-पोषण कर रहा है, जो काँ बेहद असमानता भरा है।
- जनसंख्या की यह वृद्धि आर्थिक विकास के मार्ग को अवरुद्ध करती है।

इसमें कोई दो राय नहीं कि राषट्र के विकास में जनसंख्या की महती भूमिका होती है और वशि्व के सभी संसाधनों में सर्वाधिक शक्तिशाली और सर्वप्रमुख संसाधन मानव संसाधन है। परंतु जनसंख्या वसिफोट की स्थिति कसिी भी राषट्र की सेहत के लिये ठीक नहीं है। ऐसे में आवश्यक है कि भारत जनसंख्या की तीव्र वृद्धि को रोकने के लिये ठोस नीति को आकार दे। जनसंख्या एक बार काबू में आ गई तो गरीबी, बेकारी, बेरोज़गारी, कुपोषण और भुखमरी जैसी समस्याओं का स्वतः ही अंत हो जाएगा।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/inconsistent-and-uneven-development-in-india>

